कृषकों को पर्याप्त कृषि प्रदान करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कथित असफलता

878. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकाचिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों कृषकों को पर्याप्त मात्रा में कृषि ऋण प्रदान करने में असफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि ऋणों की राशि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को सीधे दिये जाने वाले वित्त की मात्रा तथा खातों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जैसा कि इन आंकड़ों में देखा जा सकता है :—

(करोड़ रुपयों में)

	खातों की संख्या	शेष बकाया रकम
जून 1969 . . .	1,60,020	40.25
जून 1970 . . .	6,15,952	153.45
जून 1971 . . .	8,05,630	197.40
जून 1972 . . .	9,24,780	231.50
जून 1973 . . .	*11,94,387	285.06

अन्तिम

इस वृद्धि के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार कृषि क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर जोर देते रहे हैं। बैंकों द्वारा बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोली जा रही हैं, और अपने संगठन सम्बन्धी ढांचे को सुदृढ़ कर रहे हैं तथा ऋणों और प्रभावकारी ढंग से विस्तार करने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने ऋण के लिए आवेदनपत्र के फार्मों और ऋण देने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अब फार्म हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में छापे जाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी संस्थाओं के वित्त पोषण की योजना का विस्तार और अधिक राज्यों में कर दिया गया है। इन अधिकरणों के साथ छोटे किसान विकास अभिकरण/सीमांतिक किसान और कृषि श्रमिक क्षेत्रों में अधिक समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि अधिक संख्या में अभिज्ञात छोटे/सीमांतिक किसानों और कृषि श्रमिकों को इसके अन्तर्गत शामिल किया जा सके। अधिकांश बैंकों ने ब्याज की विभेदी दर योजना के अन्तर्गत किसानों के हकदार वर्गों को ब्याज की कम दर पर ऋण उपलब्ध

करने के अलावा भूमि के ग्रामकर के अनुसार ब्याज की रियायती दर की योजना भी लागू कर दी है ।

Proposal to take over wool trade

879. SHRI ARVIND M. PATEL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state whether Government are considering a proposal to take over the wool trade or to issue instructions to the manufacturers to fix prices for their production and print the prices accordingly?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): No, Sir.

Soyabean oil mixed up with sea water.

880. SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI SHRIKISHAN MODI:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether four thousand tonnes of soyabean oil got mixed up with sea water in transit from a foreign country on way to India and whether the mix-up was detected only while unloading the oil at Bombay harbour in the 3rd week of August, 1973;

(b) whether the vanaspati manufacturers have refused to accept this oil; and

(c) whether the State Trading Corporation has brought this matter to the notice of Government and if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir. The Soyabean oil was allowed to be allotted to the Vanaspati manufacturers after physical separation of sea water and necessary processing and declaration thereafter of the oil as fit for human consumption by the Municipal Health authorities.

Integrated long-term textile policy

881. SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI SHRIKISHAN MODI:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering the question of laying down an integrated long-term textile policy; and

(b) if so, the main features thereof and when the final decision is likely to be taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is still under consideration.

Complaint from Norway regarding reception given by Cochin Customs to its Fishing Vessel

883. SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI SHRIKISHAN MODI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Norway had lodged a complaint with the Government of India about the alleged rude reception given by the Cochin Customs to a fishing vessel gifted by it to India in the first week of September, 1973 and

(b) if so, the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): (a) No written complaint in the matter has been made. However, an oral report was made by the Norwegian Embassy regarding the delay which had taken place in the clearance of the gift equipment and personal effects of the crew, and the inconvenience caused thereby.